राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 144

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 2 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सूर्यास्त- 5:36 (आज) सूर्योदय- 6:34 (कल)

सरोकार

इस एमबीए सरपंच के कार्य बने विवि पाठ्यक्रम का हिस्सा

बड़नगर : उज्जैन के बड़नगर की भिड़ावद पंचायत में एमबीए पास युवा सरपंच

द्वारा गांव की बेहतरी के लिए किए काम चित्रकूट ग्रामोदय विवि के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए। विवि के स्नातक पाठ्यक्रम में इस सरपंच की उपलब्धियों को पढ़ाया जा रहा है। (पेज-10)

जागरण विशेष

'स्टार्टअप इंडिया' का गढ़ बनने की प्रतीक्षा में लखनऊ

लखनऊ : लखनऊ में 200 से अधिक क्षमतावान स्टार्टअप नए ट्रेंड की बानगी दे रहे

हैं। उच्चशिक्षित युवा उद्यमियों का कहना है कि नव उद्यम के लिए लखनऊ सोने की खान है। यदि चीजें थोड़ी और बेहतर हो जाएं तो तस्वीर बदल जाएगी। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

कश्मीर पर भारत के पक्ष में खुलकर आए अमेरिकी सांसद

नई दिल्ली : यूरोपीय संघ के सांसदों के बाद अमेरिकी सांसद भी कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का खुलकर समर्थन करने लगे हैं। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के सदस्य जार्ज होल्डिंग ने कश्मीर पर मोदी सरकार के फैसले की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, भारत सरकार का यह फैसला इस क्षेत्र के भविष्य के लिए अच्छा है।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 7

करतारपुर के लिए भारतीयों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं

इस्लामाबाद : पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत से करतारपुर आने वाले सिखों के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। उन्हें दस दिन पूर्व रजिस्ट्रेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, उद्घाटन समारोह और गुरु नानक देव की 550वीं जयंती पर किसी से कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

त्योहारों में मारुति पर चढ़ी रंगत, कई कंपनियां बेरंग

नई दिल्ली : त्योहारी सीजन पर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री सात महीने बाद बढ़ी है। बिक्री में सुधार के बावजूद ह्युंडई, टोयोटा और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री पिछले साल के इसी माह के मुकाबले बढ़ी नहीं है बल्कि कम ही रही है। हां, पिछले कुछ महीनों में मांग में गिरावट की रफ्तार अब धीमी हुई है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

इमरान को पद छोड़ने के लिए दो दिन का अल्टीमेटम

इस्लामाबाद : पाकिस्तान में कट्टरपंथी मौलाना फजलुर रहमान के नेतृत्व में गोलबंद हुए विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान को दो दिन के भीतर पद छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। सरकार के खिलाफ आजादी मार्च का नेतृत्व करने वाले फजलुर रहमान ने कहा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के धैर्य की परीक्षा लिए बिना 'पाकिस्तान के गोर्बाचेव' को इस्तीफा देना ही होगा।

गैस चैंबर बना दिल्ली-एनसीआर, हेल्थ इमरजेंसी घोषित

कड़े कदम ▶ पांच नवंबर तक निर्माण कार्यों पर रोक, दिल्ली के स्कूलों में छुट्टी, ईपीसीए ने कहा, स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत

कहा- हालात खराब, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति अति गंभीर स्थिति में पहुंच जाने के कारण पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। मौजूदा स्थिति को गैस चैंबर बताते हुए स्वास्थ्य के प्रति अतिरिक्त सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। साथ ही तमाम तरह के प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर प्रतिबंधों पर अमल सुनिश्चित करने को कहा गया है। दिल्ली में पांच नवंबर तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

इस साल जनवरी के बाद पहली बार दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बिगड़कर आपातस्थिति में पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बने ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल ने शुक्रवार को उक्त सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा कि गुरुवार रात दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता बहुत खराब हो गई और अब उससे भी आगे खतरनाक श्रेणी में पहुंच रही है। हम इसे जनस्वास्थ्य आपातकाल की तरह ले रहे हैं क्योंकि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव होगा, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर।

पंजाब सरकार की पराली न जलाने की अपील का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ है। अकेले बटिंडा जिले में अब तक 1342 स्थानों पर पराली जलाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। खेत में पराली को आग लगाता एक किसान। जागरण

> प्रदूषण की यह स्थिति स्थानीय कारकों, दिवाली की रात जलाए गए पटाखों, पराली के धुएं और मौसमी परिस्थितियों का मिश्रित परिणाम है।
>
> -भूरेलाल, अध्यक्ष, ईपीसीए

> पड़ोसी राज्यों में पराली जलने से धुएं के कारण दिल्ली एक गैस चैंबर में बदल गई है। जरूरी है कि लोग अपनी रक्षा करें, मास्क पहनें
>
> -अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

दिल्ली के प्रदूषण में पराली की हिस्सेदारी 46 फीसद तक

दिल्ली के प्रदूषण में शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से निकले धुएं की हिस्सेदारी 46 फीसद तक पहुंच गई। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था 'सफर' के मुताबिक, दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट का यह इस साल का सर्वाधिक स्तर है। 'सफर' ने कहा कि पंजाब और हरियाणा सरकारों द्वारा की गई अपीलों का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ ह। दोनों राज्यों में पराली जलाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और यह इस साल के सर्वाधिक स्तर (3,178 मामले) पर हैं। इसके अलावा निचले स्तर पर हवा की गति, धूल का उड़ना और कम आर्द्रता जैसे कुछ अन्य कारण भी हैं जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं।

कुछ दिनों में हालात सुधरने की संभावना

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) ने कहा है कि मौसम विभाग ने कुछ दिनों में हालात सुधरने की संभावना जताई है, लेकिन तब तक हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा जा सकता। इसीलिए एहतियातन दिल्ली एनसीआर में पांच नवंबर तक विभिन्न प्रतिबंधों की घोषणा की गई है। ईपीसीए ने सभी राज्यों से प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर सख्ती बरतने, निगरानी बढ़ाने, धूल उड़ने से रोकने और कचरा जलाने की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने को कहा है।

5 नवंबर की सुबह तक के लिए लगाए ये प्रतिबंध

- दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी।
- एनसीआर के सभी शहरों में हॉट मिक्स प्लांट और स्टोन थ्रेसर के परिचालन पर भी रोक रहेगी।
- दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ और भिवाड़ी में ऊर्जा संयंत्रों को छोड़कर सभी कोयला आधारित और गैर-पीएनजी औद्योगिक इकाइयां बंद रहेंगी।
- इन पूरी सर्दियों के लिए पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।

नोएडा व गाजियाबाद सर्वाधिक प्रदूषित

शहर	एयर इंडेक्स
दिल्ली	484
फरीदाबाद	479
गाजियाबाद	496
नोएडा	499
ग्रेटर नोएडा	496
गुरुग्राम	469

ईपीसीए ने कहा, लोगों को जागरूक करें राज्य

ईपीसीए के मुताबिक, जब हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 सहित सभी प्रदूषक तत्वों की मात्रा अति गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है। दमा और एलर्जी से पीड़ित मरीजों की समस्याएं इन दिनों काफी बढ़ जाती हैं। जहरीली गैसें बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर तेजी से वार करती हैं। इसीलिए लोग घरों में ही रहें। सभी राज्य इसको लेकर जनता में व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाएं।

लोगों का दम घुट रहा, सरकारें आरोप-प्रत्यारोप में उलझीं

नई दिल्ली : प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लोगों का दम घुट रहा है, लेकिन इस हालात को रोकने के लिए जिम्मेदार सरकारें आरोप-प्रत्यारोप में उलझी हुई हैं। दिल्ली सरकार का खुला आरोप है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाए जाने के कारण राजधानी इस स्थिति में पहुंची है। वहीं, हरियाणा सरकार आंकड़ों के सहारे दावा कर रही है कि वह इसके लिए कतई जिम्मेदार नहीं है। (पेज-2 भी देखें)

भाजपा ने दी महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की धमकी

ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई

- शिवसेना ने कहा, अपना मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएगी पार्टी

शिवसेना के कड़े रुख को देखते हुए भाजपा ने शुक्रवार को शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार नहीं बन पाने की स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत भी दे दिए। जबकि शिवसेना अब भी ढाई साल के मुख्यमंत्री पद की अपनी मांग पर अड़ी हुई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कह दिया है कि इस बार शिवसेना अपना मुख्यमंत्री बनाकर दिखाएगी।

माना जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत भाजपा ने शिवसेना को समझाने के अंतिम अस्त्र के तौर पर दिए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे सुधीर मुनगंटीवार ने शुक्रवार को एक चैनल से बात करते हुए कहा कि राज्य की जनता ने सरकार बनाने का जनादेश भाजपा, शिवसेना और अन्य मित्रदलों के महागठबंधन को दिया है। भाजपा ऐसी सरकार बनाने का पूरा प्रयास कर रही है और 100 फीसद ऐसी सरकार बनेगी। लेकिन यदि सरकार नहीं बन पाई तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

हालांकि, शिवसेना अब भी अपने लिए ढाई साल के मुख्यमंत्री पद की मांग पर

सुधीर मुनगंटीवार

संजय राउत

अड़ी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने अब तक सरकार बनाने की बातचीत शुरू नहीं करने की जिम्मेदारी भाजपा पर डालते हुए कहा कि राज्य में शिवसेना का मुख्यमंत्री बनकर रहेगा। राउत ने अपने ट्विटर संदेश में एक शेर लिखा है, 'साहब, मत पालिए अहंकार को इतना, वक्त के सागर में कई सिकंदर डूब गए।' इस शेर में उन्होंने 'साहब' कहकर किसे संबोधित किया है, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। लेकिन शिवसेना के तीखे तेवरों के बावजूद माना जा रहा है कि भाजपा-शिवसेना मिलकर ही राज्य में सरकार बनाएंगे। इस संबंध में शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के सरकारी आवास 'वर्षा' पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक भी बुलाई गई थी।

राकांपा बोली, विकल्प देने का करेगी प्रयास

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि यदि भाजपा-शिवसेना राज्य में सरकार बनाने में विफल रहती हैं तो उनकी पार्टी विकल्प देने का प्रयास करेगी। मुनगंटीवार के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मलिक ने कहा कि यह बयान कुछ धमकी जैसा लगता है। लोगों ने भाजपा-शिवसेना को सरकार बनाने को कहा है। यदि वे सदन के पटल पर ऐसा करने में विफल रहती हैं तो हम विकल्प देने का प्रयास करेंगे। हालांकि एक दिन पहले ही राकांपा विधायक दल के नेता चुने गए अजीत पवार कह चुके हैं कि जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और वे विपक्ष में ही बैठेंगे।

शिवसेना को समर्थन के मुद्दे पर कांग्रेस में दो मत

कांग्रेस में भी वैकल्पिक सरकार बनाने या शिवसेना को समर्थन देने पर दो मत नजर आ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चह्वाण चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शिवसेना को सरकार बनाने के लिए उकसाते दिख रहे हैं। वहीं, प्रदेश के प्रभारी महासचिव मल्लिकार्जुन खड़गे सहित बाकी सभी वरिष्ठ नेतागण विपक्ष में बैठने की बात कर रहे हैं। दिल्ली गए वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया से मुलाकात के बाद स्पष्ट कर दिया है कि किसी अन्य दल को समर्थन देने के मुद्दे पर आलाकमान से उनकी किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। (पेज-4 भी देखें)

वाट्सएप ने छिपाई सरकार से जासूसी की जानकारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सरकार को संदेह, संदेशों का स्रोत बताने से बचने के लिए कंपनी जासूसी मामले से बना रही दबाव
- जुलाई और सितंबर आइटी मंत्री से मिले थे वाट्सएप के दो शीर्ष अधिकारी

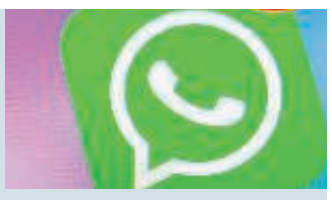

संदेशों का स्रोत बताने के लिए भारत के बाद अन्य देशों से दबाव बनने के बाद वाट्सएप पर शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार सामने आए जासूसी मामले को इसी शिकंजे से निकलने की वाट्सएप की कोशिश के तौर पर देख रही है। सरकार ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि इस साल जून के बाद कम से कम दो बार वाट्सएप के शीर्ष अधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से मुलाकात की, जासूसी मामले का जिक्र तक नहीं किया। जबकि आइटी एक्ट के मुताबिक ऐसा करना उसके लिए बाध्यकारी है। सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि जासूसी मामले से चर्चा में आए स्पाइवेयर पेगासस को खरीदने को लेकर इजरायली कंपनी से किसी भी तरह की बातचीत नहीं चल रही है।

सरकार के एक उच्च अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि क्या इस घटना को सरकार की तरफ से वाट्सएप की जवाबदेही और संदेशों का स्रोत बताने के संबंध में बनाए जा रहे कानून से बचने के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए? अधिकारी ने कहा कि जासूसी के शिकार लोगों के नामों को देखें तो उनमें अधिकांश ऐसे हैं जो मौजूदा सरकार के आलोचक हैं। ऐसे में सरकार का कहना है कि क्या यह महज एक संयोग है?

सरकार बीते दो साल में लिंचिंग और हिंसा की घटनाओं को लेकर वाट्सएप के जरिए फैलाए जा रहे संदेशों पर रोक लगाने के लिए कई बार कंपनी को चेतावनी दे चुकी है। सरकार चाहती है कि वाट्सएप जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को ऐसे संदेशों के स्रोत तक पहुंचने में मदद करे। लेकिन वाट्सएप हर बार यूजर की निजता की आड़ लेकर ऐसा करने से बचती रही है।

जानकारी देने की बाध्यता : सूत्रों ने बताया कि देश के आइटी अधिनियम की धारा 70 के मुताबिक अगर यूजरों के अकाउंट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ होती है तो वाट्सएप इसकी जानकारी देने के लिए बाध्य है। इस साल जुलाई में वाट्सएप के ग्लोबल हेड विल कैचकार्ट और सितंबर में फेसबुक के वैश्विक मामलों के उपाध्यक्ष निक क्लेग ने सरकार के उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इनमें से किसी एक भी बैठक में वाट्सएप अधिकारियों ने जासूसी संबंधी किसी भी जानकारी का जिक्र तक नहीं किया।

जासूसी कांड के सामने आने के समय पर सवाल : सरकार जासूसी कांड के सामने आने के समय पर भी सवाल खड़ा कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार अपने आइटी कानून को और सख्त बनाने जा रही है। संसद के अगले सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने का समय मांगा था। सूत्रों का मानना है कि कानून बनने के बाद वाट्सएप के लिए संदेशों के स्रोत की जानकारी देने के लिए बहानेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा।

वाट्सएप ने कहा, भारत सरकार के विरोध पर उठाए सख्त कदम पेज>>7

भारत व जर्मनी की मित्रता और व्यापक होगी

नई दिल्ली : भारत ने स्पष्ट करदिया है फ्रांस व जर्मनी उसकी भावी रणनीति में सबसे अहम होंगे। शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी और चांसलर एंजेला मर्केल के बीच हुई वार्ता और आधिकारिक स्तर की बातचीत में रिश्तों को जिस तरह से व्यापक बनाने पर चर्चा हुई है, वह भारत की रणनीति को बताता है। जर्मनी ने भी कहा है कि उसकी एशिया नीति में भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी होगा। दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। (पेज-3)

पांच चरणों में होंगे झारखंड विधानसभा के चुनाव

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि राज्य में 81 विधानसभा सीटों के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में चुनाव होंगे। परिणाम 23 दिसंबर को आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। राज्य में 2014 के विधानसभा चुनाव भी पांच चरणों में हुए थे। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी तक है। (पेज-4)

छत्तीसगढ़ में जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी भूपेश सरकार

नईदुनिया, रायपुर

- जिला संवर्ग के पदों में भर्ती आरक्षण नियम में संशोधन नियामावली तय करने को कैबिनेट की मंजूरी
- सरकार का तर्क, कुछ जिलों में सौ फीसद से अधिक हो जाता आरक्षण, इस वजह से किया जाएगा बदलाव

छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार जातिगत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देगी। भूपेश कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में जिला संवर्ग के पदों पर भर्ती आरक्षण में बदलाव पर मुहर लगा दी गई। इसके लिए सरकार नई नियमावली तैयार करेगी। सरकार के इस निर्णय का असर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और गरीब सवर्णों के कोटे पर पड़ेगा।

कैबिनेट में हुए इस फैसले की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने इसी वर्ष लोक सेवा भर्ती नियम के तहत आरक्षण में बदलाव किया था। इसके तहत अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 से बढ़कर 13, अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 से बढ़कर 27 तथा अनुसूचित जनजाति का 32 फीसद रखते हुए गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने का फैसला किया था। इस नियम के लागू होने से कुछ जिले जहां जिला संवर्ग के पदों में भर्ती में पहले से आरक्षण लागू है, वहां आबादी के अनुपात में आरक्षण सौ फीसद से अधिक हो जाता। विशेष रूप से आदिवासी बाहुल्य बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर समेत कुछ और जिले शामिल हैं। इसी वजह से सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे जिलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में तो कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ओबीसी और गरीब सवर्णों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव होगा।

हाई कोर्ट ने लगा रखी है रोक : भूपेश सरकार ने पिछले दिनों लोक सेवा आयोग के पदों पर भर्ती में बढ़ा हुआ कोटा लागू कर दिया था। गरीब सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण को मिलाकर सूबे में आरक्षण 82 फीसद पहुंच गया था। इसके खिलाफ हुई अपील पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बढ़ाए गए आरक्षण पर रोक लगा रखी है।

जेएनयू के हॉस्टलों में रहने वाले छात्रों को भरना होगा बिजली-पानी का बिल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) कैंपस में बने छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को अब बिजली-पानी समेत अन्य बिल भरने होंगे। इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेशन (आइएचए) कमेटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया है। पहले किसी भी प्रकार का बिल नहीं लिया जाता था।

जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार ने कहा कि कैंपस के 16 छात्रावासों में रह रहे करीब पांच हजार छात्रों द्वारा बिजली, पानी, सर्विस समेत अन्य बिलों का भुगतान नहीं किया जाता था। इससे जेएनयू पर सालाना 10 करोड़ रुपये का खर्च आता था। उन्होंने कहा, अब तक सिर्फ सुबासीर एवं यमुना छात्रावास में रहने वाले शादीशुदा शोधार्थियों द्वारा ही बिजली, पानी एवं अन्य बिल दिए जाते रहे हैं।

जेएनयू प्रशासन ने यह भी कहा है कि छात्रावास के नियमों और ड्रेस कोड को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। नए नियमों के तहत, किसी भी तरह के ड्रेस कोड को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ डाइनिंग हॉल पर सभी को व्यवस्थित कपड़ों में आने के निर्देश दिए गए हैं।

फैसला जो भी हो, सामाजिक व धार्मिक सौहार्द पर जोर देगा संघ

नई दिल्ली : इस माह के मध्य तक राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि फैसला जो भी आए, देश का सामाजिक-धार्मिक सौहार्द नहीं बिगड़ना चाहिए। इसके लिए हिंदू पक्ष से संयमित रहने का आग्रह करने के साथ ही सिंघ वभिन्न धर्म के प्रमुख लोगों से मुलाकात का क्रम जारी रखेगा। इसमें संघ के करीबी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। (पेज-6)

चांद के बाहरी वायुमंडल में मिला आर्गन-40

चेन्नई : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चंद्रयान-2 के विक्रम आर्बिटर से संपर्क ना होने की परेशानी भले ही ना दूर हुई हो, लेकिन अब चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चंद्रमा के बाहरी वातावरण में आर्गन-40 का पता लगा लिया है। इसरो ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इस अध्ययन के लिए स्वदेशी चंद्रयान-2 आर्बिटर पर चंद्र एटमॉसफीयरिंग कंपोजिशन एक्सप्लोरर-2 (सीएचएसई-2) पेलोड मौजूद है। (पेज-16)

बनाया कीर्तिमान

अदालतों में लंबित मुकदमों के बारे में बातें आए दिन होती रहती हैं, लेकिन यह समाचार सुकून देने वाला है, कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश ने अपने काम से नजीर कायम की है

एक जज ने 15 साल में निपटाए सवा लाख मुकदमे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- सुधीर अग्रवाल देश के एकमात्र न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इतने मुकदमों का निस्तारण किया

देश की अदालतों में लंबित मुकदमों और न्याय मिलने में देरी की चर्चाओं के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने मुकदमों के निस्तारण के मामले में नया कीर्तिमान बनाया है। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने 15 साल के कार्यकाल में 31 अक्टूबर 2019 तक कुल 1,30,418 मुकदमों का निपटारा किया है। वह देश के एकमात्र न्यायाधीश हैं, जिन्होंने इतने मुकदमों पर फैसला देने का रिकार्ड बनाया है। उल्लेखनीय है कि अग्रवाल ने कई चर्चित मामलों में निर्णय देकर नजीर भी पेश की है।

मूलरूप से फीरोजाबाद के रहने वाले न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने स्नातक आगरा विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद मेरठ विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। पांच अक्टूबर 1980 से उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत करके करियर की शुरुआत की। उन्होंने टैक्स मामलों में वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही उनकी विशेषज्ञता सर्विस और इलेक्ट्रिसिटी मामलों में भी हो गई। वह उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के स्टैंडिंग काउंसिल(वकील) भी रहे। 19 सितंबर 2003 को उत्तर प्रदेश सरकार

सुधीर अग्रवाल फाइल फोटो

के अपर महाधिवक्ता नियुक्त किए गए। फिर अप्रैल 2004 को उनको वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया। अग्रवाल ने पांच अक्टूबर 2005 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अपर न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। इसके बाद 10 अगस्त 2007 को वह हाईकोर्ट के नियमित जज नियुक्त किए गए। देश की न्यायपालिका में अगर ऐसे न्यायाधीशों की संख्या बढ़ जाए तो अदालतों में मुकदमों का फैसला लंबे समय तक रुका नहीं रहेगा।

चर्चित निर्णय

- श्रीराम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर निर्णय सुनाकर ख्याति अर्जित की
- ज्योतिष पीठ में शंकराचार्य पद के विवाद पर निर्णय सुनाया।
- मंत्रियों और सरकारी अफसरों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का निर्देश दिया
- सरकारी कर्मियों को सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराने का निर्देश दिया
- अवैध कब्जे वाली नजूल भूमि को मुक्त कराकर सरकार के कब्जे में देने का निर्देश दिया
- धरना-प्रदर्शन के दौरान संपत्ति के नुकसान की वसूली का आदेश दिया
- शंकरगढ़ की रानी से 45 गांव मुक्त कराने का आदेश दिया

उप्र के सीआरपीएफ सेंटर पर आतंकी हमले में छह दोषी करार

जागरण संवाददाता, रामपुर

- 31 दिसंबर 2007 की रात हमले में सात जवान हो गए थे शहीद
- आरोप सिद्ध न होने पर दो बरी, आज कोर्ट सुना सकती है सजा

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर पर करीब 12 साल पहले हुए आतंकी हमले के मामले में जिला अदालत ने छह को दोषी करार दिया है। इनमें एक पाकिस्तानी और एक गुलाम कश्मीर का नागरिक शामिल हैं। अपर जिला सत्र न्यायाधीश संजय कुमार (तृतीय) ने आरोप सिद्ध न होने पर दो अभियुक्तों को दोषमुक्त करार दिया है। अदालत इस मामले में शनिवार को सजा का ऐलान कर सकती है।

उल्लेखनीय है कि सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात ढाई बजे आतंकियों ने हमला कर दिया था। आतंकी दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर स्थित सेंटर के गेट नंबर एक से अंदर घुसे थे। गेट पर मौजूद जवानों पर एके-47 से फायरिंग कर रहे आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे। इसके बाद परिसर में काफी अंदर तक घुस गए थे। हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा गेट के बाहर सो रहे एक रिक्शा चालक की भी मौत हो गई थी। पुलिस ने हमले के आरोप में आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें गुलाम कश्मीर निवासी इमरान शहजाद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मुहम्मद फारुख, बिहार का सबाउद्दीन, महाराष्ट्र के गोरे गांव निवासी फहीम अंसारी, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का मुहम्मद कौसर, बरेली जिले का गुलाब खां, मुरादाबाद के मिलक कामरू का जंग बहादुर बाबा और रामपुर का मुहम्मद शरीफ शामिल थे। इन सभी को पुलिस ने 10 फरवरी 2008 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सुरक्षा के मद्देनजर इन्हें लखनऊ और बरेली की जेलों में बंद किया गया था।

38 की हुई गवाही पेज>>5